दैनिक
न्याय साक्षी
अधिकार से न्याय तक

आवश्यक सूचना

आप सभी को सूचित करते हर्ष हो रहा है, कि न्यायसाक्षी अधिकार से न्याय तक का सर्वे का कार्य तेजी से चल रहा है, जल्द ही सर्वे की टीम आपके घर विजिट करेगी, कृपया अपनी प्रति सुरक्षित कराएं।

RNI NO - CHHHIN/2018/76480 || Postal Registration No-055/Raigarh DN CG || रायगढ़, गुरुवार 10 जून 2021 || पृष्ठ-4, मूल्य 3 रूपए || वर्ष-03, अंक- 250

महत्वपूर्ण एवं खास

कृषि कानूनों के निरस्त होने पर ही खत्म होगा किसान आंदोलन : कांग्रेस

नई दिल्ली (आरएनएस)। कांग्रेस ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करना ही किसान आंदोलन के मुद्दे का एकमात्र समाधान है। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान 500 किसानों की मौत होने के दावे वाले हैशटैग के साथ ट्वीट किया कि खेत-देश की रक्षा में तिल-तिल मरे हैं किसान, पर ना डरे हैं किसान, आज भी खरे हैं किसान। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि किसान को भीख नहीं, न्याय चाहिए। किसान को अहंकार नही, अधिकार चाहिए । घमंड के सिंहासन से उतरिए, राजहठ छोड़िए, तीनों काले क़ानून ख़त्म करना ही एकमात्र रास्ता है। गौरतलब है कि पिछले कई महीनों से कई किसान संगठन दिल्ली के निकट कुछ स्थानों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांग तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देने की है।

जन्मदिन मनाकर लौट रहे लोगों की बाईक ट्रक से टकराई, 3 की मौत

बैतूल (आरएनएस)। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में जन्मदिन की पार्टी में शामिल होकर लौट रहे लोगों की मोटर साइकिल सामने खड़े ट्रक में जा घुसी। इस हादसे में एक युवती सहित तीन लोगों की मौत हो गई। साईखेड़ा थाना के प्रभारी रत्नाकर हिंगवे ने बताया, मोनू उइके, दीपिका धुर्वे, बबलू उइके एवं एक अन्य युवक एक ही बाइक पर मुलताई से जन्मदिन मनाकर घर लौट रहे थे। बीती रात को तेज बारिश का दौर जारी था। इसके बावजूद बाइक सवार कहीं रुके नहीं। इस दौरान बैतूल-मुलताई मार्ग पर स्थित ससुन्दरा चेक पोस्ट बेरियर के पास सड़क किनारे खड़े ट्रक में बाईक जा टकराई। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हादसा काफी हृदय विदारक था। दो युवक और किशोरी की मौके पर ही मौत हो गई। एक अन्य गम्भीर से घायल हुए युवक को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। उसकी स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है।

यूपी के कानपुर में लोडर को बस ने मारी टक्कर, 16 की मौत

कानपुर (आरएनएस)। उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर से कुछ दूर सचेंडी थाना क्षेत्र के पास तेज से जा रही एक बस ने लोडर को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में 16 लोगों की मौत हो गई। कानपुर रेंज के आईजी से मिली जानकारी के अनुसार यह घटना सचेंडी थाना क्षेत्र जो कि कानपुर आउटर में पड़ता है। इस घटना में लोडर और बस की आमने सामने टक्कर होने से 16 की मौत और 5 घायल हो गए हैं। घायलों का इलाज हैलट में चल रहा है। कुछ लोग इसमें सचेंडी के गांव से चढ़े थे। यह बिस्कुट फैक्टरी में काम करते थे। यह बस लखनऊ से दिल्ली की तरफ जा रही थी। यह प्राइवेट बस थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर के सचेंडी क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने दुर्घटना में मृतकों के परिजनों को 02-02 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए दिवंगत आत्मा की शांति की कामना की है। मुख्यमंत्री ने इस सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हुए समुचित इलाज की व्यवस्था करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि उच्चाधिकारी मौके पर पहुंचकर युद्धस्तर पर राहत कार्य सुनिश्चित कराएं। उन्होंने जिला प्रशासन को दुर्घटना के कारणों की जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को बस और टेम्पो की भिड़ंत में करीब 16 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में कई अन्य लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज हैलट में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासनिक अलमा चौकन्ना हो गया। आनन-फानन पुलिस की गाड़ियों और सचेंडी पीएचसी-सीएचसी से एंबुलेंस मौके पर पहुंची। गाड़ियां पलटते ही उसमें बैठी सवारियों में चीख-पुकार मचने लगी। इस भयावह दृश्य को वहां मौजूद जिस किसी शख्स ने भी देखा उसके होश ही उड़ गए। लोग मदद के लिए आगे भी आए। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने देर न करते हुए पुलिस और कंट्रोल रूम को हादसे की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने टेंपो के अंदर फंसे गंभीर रूप से घायलों को सबसे पहले बाहर निकाला। इसके बाद घटनास्थल पर पहुंची दर्जनभर एंबुलेंस सभी को लेकर लाला लाजपत राय एलएलआर अस्पताल रवाना हुई।

देश में कोरोना का कहर ढलान पर आया, 24 घंटे में 92,596 नए मामले, 2,219 की मौत

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना का कहर अब ढलान पर है और पिछले दो दिन से दैनिक मामलों की संख्या एक लाख से नीचे दर्ज की जा रही है। हालांकि इसमें पिछले एक दिन में नए मामलों व मौतों में मामूली इजाफा देखा गया है, लेकिन वहीं कोरोना से ठीक होने वालों की संख्या भी तेजी से बढ़ती नजर आ रही है। मसलन पिछले 24 घंटे में 92,596 नए मामले दर्ज किये गये, तो वहीं कोरोना संक्रमण की वजह से 2,219 लोगों ने अपनी जान गंवाई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,90,89,069 हो गई। देश में लगातार दूसरे दिन एक लाख से कम नए मामले सामने आए हैं और उपचाराधीन सक्रीय मरीजों की

संख्या कम होकर 12,31,415 हो गई है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण से 2,219 और लोगों की मौत के बाद मृतक संख्या बढ़कर 3,53,528 हो गई है।

❐ **महाराष्ट्र में ज्यादा मौतें-** मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में जिन 2,219 लोगों की संक्रमण से मौत हुई, उनमें से महाराष्ट्र के 702 , तमिलनाडु के 409, कर्नाटक के 179 और केरल के 124 लोग थे। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश में संक्रमण से अभी तक कुल 3,53,528 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से महाराष्ट्र के 1,01,172 लोग, कर्नाटक के 32,099 लोग, तमिलनाडु के 27,765 लोग, दिल्ली के 24,668 लोग, उत्तर प्रदेश के 21,425 लोग, पश्चिम बंगाल के 16,460 लोग , पंजाब के 15,219 लोग और छत्तीसगढ़ के 13,257 लोग थे।

❐ **सक्रीय मरीजों की संख्या में कमी-** देश में कोविड-19 के 92,596 नए मामले, उपचाराधीन मरीजों की संख्या घट कर 12,31,415 रह गई है, जो कुल मामलों का 4.23 प्रतिशत है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मामलों में कुल 72,287 की कमी आई है। मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 94.55 प्रतिशत है। संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या लगातार 27वें दिन संक्रमण के नए मामलों से अधिक रही। आंकड़ो के अनुसार, देश में अभी तक कुल 2,75,04,126 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं, कोविड-19 से मृत्यु दर 1.22 प्रतिशत है। आंकड़ों के अनुसार देश में अभी तक कुल 37,01,93,563 नमूनों की कोविड-19 संबंधी जांच की गई है, जिनमें से 19,85,967 नमूनों की जांच मंगलवार को की गई। नमूनों के संक्रमित आने की दैनिक दर 4.66 प्रतिशत है, पिछले 16 दिन से संक्रमण की दैनिक दर 10 प्रतिशत से कम बनी हुई है। वहीं संक्रमण की साप्ताहिक दर भी कम होकर 5.66 प्रतिशत हो गई है। देश में पिछले साल सात अगस्त को संक्रमितों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त को 30 लाख और पांच सितम्बर को 40 लाख से अधिक हो गई थी। वहीं, संक्रमण के कुल मामले 16 सितम्बर को 50 लाख, 28 सितम्बर को 60 लाख, 11 अक्टूबर को 70 लाख, 29 अक्टूबर को 80 लाख, 20 नवम्बर को 90 लाख के पार हो गए। देश में 19 दिसम्बर को ये मामले एक करोड़ के पार और चार मई को दो करोड़ के पार चले गए थे।

राज्यों के पास 1.33 करोड़ से अधिक वैक्सीन की खुराक अब भी मौजूद : केंद्र

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीकों की 1.33 करोड़ से अधिक खुराक अब भी मौजूद हैं तथा तीन लाख से अधिक खुराकें अगले तीन दिन के भीतर उन्हें मिल जाएंगी। अब तक राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को 25 करोड़ से अधिक खुराकें दी गई हैं। ये खुराकें उन्हें भारत सरकार की ओर से निःशुल्क तरीके से तथा राज्यों द्वारा सीधे खरीद की श्रेणी में दी गई हैं।

मंत्रालय ने बुधवार सुबह आठ बजे तक उपलब्ध आंकड़ों के हवाले से बताया कि कुल 23,74,21,808 खुराकों (बरबाद हुए टीकों समेत) का इस्तेमाल हुआ है। उसने बताया, '' राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के पास कोविड-19 टीकों की कुल 1,33,68,727 खुराक अब भी मौजूद हैं। इसके अलावा, अगले तीन दिन में और 3,81,750 खुराकें उन्हें उपलब्ध करवाई जाएंगी। उल्लेखनीय है कि राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत भारत सरकार राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके दे रही है। इसके अलावा राज्य टीकों की सीधी खरीद भी कर सकते हैं। कोविड टीकाकरण का तीसरा चरण देश में एक मई को आरंभ हुआ था। महामारी से निबटने की सरकार की व्यापक रणनीति का एक अहम स्तंभ टीकाकरण है।

खरीफ की फसलों के लिए 62 प्रतिशत तक बढ़ी एमएसपी

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार ने बाजार सत्र 2021-22 के लिए खरीफ की फसलों पर एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) बढ़ाने को अनुमति दे दी। केंद्र ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले एमएसपी में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी तिल (452 रुपये प्रति कुंतल) में की गई है। इसके बाद तुअर और उड़द (दोनों 300 रुपये प्रति कुंतल) आते हैं।

केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने खरीफ की फसलों पर 50 फीसदी तक एमएसपी बढ़ाने का फैसला किया है। उन्होंने

कहा कि केंद्र सरकार पिछले सात साल से किसानों के हित में फैसले ले रही है और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए चर्चा करने के लिए हर वक्त तैयार है। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पिछले साल के मुकाबले 72 रुपये बढ़कर 1940 रुपये प्रति कुंतल हो गया है। उन्होंने कहा कि पिछले साल यह राशि 1868 रुपये प्रति कुंतल थी। उल्लेखनीय है कि एमएसपी वह दर होती है जिस दर से सरकार किसानों से खाद्यान्न खरीदती है।

❐ **इन फैसलों को भी मिली मंजूरी-** कैबिनेट ने रेलवे की संचार व सिग्नल प्रणाली उन्नत करने के लिए पांच मेगाहर्ट्ज के 4जी स्पेक्ट्रम को मंजूरी दे दी। इस पर अगले पांच साल में 25 हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड में संशोधन के साथ नई निवेश नीति (एनआईपी)-2012 की प्रायोज्यता के विस्तार को भी मंजूरी दे दी गई।

❐ **जिद छोड़े केंद्र सरकार : कांग्रेस-** वहीं केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि किसानों के आंदोलन को समाप्त करने का एक ही तरीका है कि तीनों नए कृषि कानून वापस लिए जाएं। देश के मुख्य विपक्षी दल ने इन कानूनों को विनाशकारी करार देते हुए कहा कि सरकार को अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए और किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए।

केंद्रीय कर्मियों के लिए पेंशन में देरी की तमाम दिक्कतें खत्म

» एक जुलाई से जारी होगा इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर

नई दिल्ली (आरएनएस)। केंद्र सरकार में पुरानी पेंशन व्यवस्था के तहत आने वाले लाखों कर्मियों के लिए राहत की खबर है। भारत के महालेखा नियंत्रक कार्यालय ने सभी विभागों को आदेश जारी कर दिया है कि एक जुलाई के बाद रिटायर होने वाले ऐसे कार्मिक, जिन्होंने अपना सेवाकाल पूरा किया है, उन्हें पेंशन पेमेंट ऑर्डर (पीपीओ) की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी। कर्मी को ईपीपीओ जारी होगा। यानी उन्हें

इलेक्ट्रॉनिक पेंशन पेमेंट ऑर्डर मुहैया कराया जाएगा। इससे पेंशन दस्तावेजों के खोने की टेंशन भी खत्म होगी। अनेकों ऐसी शिकायतें, जिनमें पेंशन पेपर तैयार करने वाले कर्मियों की लापरवाही सामने आती है, उन पर रोक लगेगी।

भारत के महालेखा नियंत्रक कार्यालय द्वारा जारी आदेशों में कहा गया है कि कुछ केसों में अभी पेंशन पेमेंट ऑर्डर, बतौर हार्ड कॉपी और ईपीपीओ के तौर पर जारी किया जा रहा है। रिटायर होने वाले सभी कर्मियों के मामले में ईपीपीओ सुविधा का इस्तेमाल शुरू नहीं हुआ है। जिन मामलों में पीपीओ, बुक के आकार में और इलेक्ट्रॉनिक आधार पर जारी हुआ है, उन दोनों का मिलान किया जाएगा। उनकी जांच कर यह देखा जाएगा कि उनमें कोई अंतर तो नहीं है। अगर उनमें कोई अंतर पाया जाता है तो उसे 15 जून 2021 तक ठीक कर वापस भेज दें। यह ध्यान रहे कि किसी भी सूरत में पहली जुलाई के बाद सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को पीपीओ जारी नहीं होगा। उन्हें ईपीपीओ ही इश्यू किया जाएगा।

वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि पहले उन कर्मियों के मामले में ईपीपीओ जारी किया जाए, जो अपना सेवाकाल पूरा कर रिटायर होते हैं। इसके बाद रिटायरमेंट की दूसरी श्रेणियों के मामले में ईपीपीओ जारी किया जाएगा। जैसे कोई कार्मिक, जिसे दंड की वजह से तय अवधि से पहले ही सेवा छोड़नी पड़ी हो। विकलांगता, स्वैच्छिक रिटायरमेंट या किसी अन्य कारण से सेवा में नहीं रहने वाले कर्मियों के मामले में भी ईपीपीओ योजना लागू की जाएगी। पहली जुलाई से तय श्रेणी में सौ फीसदी ईपीपीओ जारी होगा। अगर किसी विभाग को ईपीपीओ जारी करने में कोई दिक्कत हो रही है तो वह एक सप्ताह के अंदर भारत के महालेखा नियंत्रक कार्यालय को अवगत करा दे।

सांसद नुसरत जहां ने तोड़ा पति निखिल से रिश्ता

» लिखा-जब शादी मान्य नहीं तो तलाक लेने की जरूरत नहीं

कोलकाता (आरएनएस)। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और बंगाली अभिनेत्री नुसरत जहां और उनके पति निखिल जैन के रिश्ते के बीच दरार पड़ गई है। हाल ही में नुसरत जहां के प्रेग्नेंसी की खबरें सामने आई थीं, जिसपर निखिल ने कहा था कि उन्हें नुसरत के गर्भवती होने की जानकारी नहीं है। अगर ऐसा है तो वो बच्चा उनका नहीं है। वो दोनों छह महीने से साथ नहीं हैं। इसी बीच नुसरत जहां ने कहा है कि निखिल जैन संग उनकी शादी मान्य नहीं है। इसलिए तलाक लेने का सवाल ही नहीं उठता। नुसरत ने स्टेटमेंट जारी कर कई खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी शादी तुर्की के कानून के मुताबिक हुई जो कि भारत में वैध नहीं है। नुसरत ने आगे कहा कि अंतर-धार्मिक शादी के लिए स्पेशल मैरिज एक्ट की वैधता जरूरी है, जो इस मामले में नहीं हुआ। ऐसे में जब शादी वैध नहीं है तो फिर तलाक का सवाल ही नहीं उठता है। कारोबारी निखिल जैन से जून 2019 में नुसरत जहां की शादी हुई थी। नुसरत ने कहा कि हम काफी पहले एक दूसरे से अलग हो गए थे। नुसरत जहां ने ये भी बयान दिया कि उनके पति ने उनके खाते से पैसे निकाले। इस बारे में उन्होंने ये भी कहा कि बैंक से भी उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि वे अपने पति निखिल से काफी पहले अलग हो गई थी।

रेलवे में अब कोविड के रोजाना मामले हुए कम, रेल कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर घोषित करने की मांग

नई दिल्ली (आरएनएस)। देश में कोरोना वायरस के संक्रमितों का आंकड़ा भी हर दिन कम होता दिखाई दे रहा है। भारतीय रेलवे से राहत भरी खबर सामने आ रही है। एक समय जहां रेलवे में रोज एक हजार कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो रहे थे, अब उनकी संख्या घटकर महज 150 तक रह गई है। हालांकि अब तक कोरोना से करीब 2600 से ज़्यादा रेलवे कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है।

रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा के अनुसार रेलवे किसी अन्य राज्य या क्षेत्र से अलग नहीं है। हम परिवहन का काम करते हैं और सामान व लोगों को लाते और ले जाते हैं। हमने भी कोविड संक्रमण की मार झेलते लोगों की मदद

की है। रेलवे कर्मचारी हमारी पूंजी है। अब तक करीब 60 फीसदी कर्मचारी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। आज कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। रोज करीब 150 कर्मचारी ही संक्रमित हो रहे हैं। हम अपने स्टॉफ का पूरा ख्याल रख रहे हैं। उन्हें आवश्यक मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध करा रहे हैं। रेलवे के अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाई गई है, रेल अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र लगाए गए हैं। फिलहाल साढ़े तीन से चार हज़ार रेलवे कर्मी या उनके परिवार के सदस्य इन अस्पतालों में भर्ती हैं। हमारा प्रयास है कि वो जल्दी ठीक हो जाएं। हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा था कि कोविड महामारी की चुनौती से लड़ने के लिये भारतीय रेल के प्रयास निरंतर जारी हैं। इसी क्रम में रेलवे हॉस्पिटल्स में 86 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही कोविड बेड्स और वेंटिलेटर्स की संख्या भी बढ़ाई गयी है। हमारे रेल कर्मचारी कोरोना महामारी के विरुद्ध इस लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर अपना योगदान दे रहे हैं। उन्होंने रेल कर्मचारियों के प्रति उनके इस योगदान के लिए आभार जताया है।

रेलवे के सबसे बड़े कर्मचारी संघ ने सोमवार को एक बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के जरिए उन्होंने मांग की है कि उन्हें फ्रंटलाइन कोविड वर्कर्स घोषित किया जाए क्योंकि वे कोरोनो वायरस संकट के दौरान लोगों की सेवा कर रहे हैं और इस प्रक्रिया में वह 2,000 से अधिक सहयोगियों को खो चुके हैं। उन्होंने अपनी मांग को और मजबूत करने के लिए ट्विटर पर इस अभियान पर लोगों का समर्थन मांगा है। एआईआरएफ के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कहा कि दिन-रात अपने कर्तव्यों का पालन करने और अपने मूल्यवान जीवन का बलिदान करने के बावजूद फ्रंटलाइन वर्कर्स के रूप में ना पहचाने जाने पर रेलवे कर्मचारियों में गंभीर अशांति और असंतोष है।उन्होंने कहा कि जहां सरकार अन्य विभागों के कर्मचारियों को फ्रंटलाइन वर्कर मानकर तमाम सुविधाएं मुहैया करा रही है, वहीं रेलकर्मियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। अगर मांगें नहीं मानी गईं और सरकार ने उन्हें वो सारे लाभ नहीं दिए जो एक फ्रंटलाइन वर्कर्स को दिए जाते हैं तो आंदोलन तेज कर दिया जाएगा।